

## आम बजट में महिलाओं के लिये क्या?

### सन्दर्भ

- इस वर्ष आम बजट के पेश किये जाने के पहले से ही यह माना जा रहा था कवित्तित्त मन्त्री अरुण जेटली अपने पटारे से देश की महिलाओं के लिये खास तोहफे निकालेंगे ।
- जहाँ महिलाओं को उम्मीद थी कसरकार इस बार आम ज़रूरत की चीज़ों के दाम न बढ़ाकर उन्हें राहत देगी, तो वहीं जानकार मान रहे थे कइस बार के बजट में स्वास्थ्य, शक्तिषा, महिला एवं बाल वकिसा जैसे अहम सामाजकि क्षेत्रों पर खर्च बढ़ सकता है ।
- सरकार ने आशा के अनुरूप कदम भी बढ़ाए हैं लेकनि कुछ वशिषज्जों का मानना है कसरकार द्वारा कयिा गया आवंटन नरिधारति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पर्याप्त नहीं होगा ।

### महिला सरोकारों के लिये आवंटन

- महिलाओं को सस्ते लोन दिये जाएंगे, इसके लिये नेशनल हाउसिंग बैंक को 20 हजार करोड़ की धनराशि उपलब्ध जाएगी । साथ ही, सस्ती कीमतों पर घर भी उपलब्ध कराए जाएंगे ।
- महिलाओं के कौशल वकिसा के लिये 1.84 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं ।
- महिला सशक्तीकरण केंद्र स्थापित किये जाएंगे । महिला सशक्तीकरण के लिये 500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं ।
- गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6000 रुपए ट्रांसफर किये जाएंगे ।
- महिला और बाल वकिसा के लिये 1,13,326 करोड़ रुपए का आवंटन कयिा गया है जो पछिले बजट में 90,769.80 करोड़ रुपए था ।

### क्या रहा उम्मीद के वपिरीत?

- वदिति हो क मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 53 लाख बताई जा रही है । लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या के मद्देनज़र बजटीय आवंटन में वृद्धि को पर्याप्त नहीं बताया जा रहा है ।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की यौन उत्पीड़न से रक्षा के लिये कोई आवंटन नहीं कयिा गया है, जो कदुरभाग्यपूर्ण है ।
- कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास नरिमाण और वृद्ध महिलाओं के लिये वशिष पेंशन जैसे महत्त्वपूर्ण वशिषों के संबंध में भी कोई आवंटन नहीं कयिा गया है ।
- वशिषज्जों द्वारा यह भी संदेह व्यक्त कयिा गया है कमहिला एवं बाल वकिसा पर उल्लेखनीय व्यय के बावजूद हो सकता है कभारत के उत्तर-पूरवी भाग से महिलाओं एवं बच्चियों के होने वाले अवैध मानव व्यापार को रोकने में सफलता न मलि ।
- शक्तिषा, संसाधन और रोज़गार के अभाव में भारत के उत्तर-पूरवी क्षेत्र की महिलाएँ आसानी से मानव तस्करों के चंगुल में फँस जाती हैं । कल्याणकारी योजनाओं के लिये आवंटन में बढ़ोत्तरी सुधार की एक लम्बी प्रक्रिया है । तत्कालीन तौर पर इस समस्या के नदिान के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं कयिा गया है ।